भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 767

(दिनांक 25.07.2023 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम

767. श्री के. मुरलीधरनः
डॉ. ए. चेल्ला कुमारः
डॉ. अमर सिंहः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम के मसौदे के पैनल के भाग के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार के अंतर-मंत्रालयीय पैनल में किसी भी डिजिटल समाचार मीडिया प्रकाशक को शामिल न करने के औचित्य का ब्यौरा क्या है जिसका उद्देश्य डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम के मसौदे को मजबूत करने में मदद करना है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर एक समिति का गठन किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग और नीति आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं और जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेंगी और यह जांच करेंगी कि क्या वे डिजिटल अर्थव्यवस्था और संबंधित मामलों से उभरी चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन और न्यूज पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को समिति के समक्ष प्रस्तुतियां बनाने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

*****